

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3352  
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

असम में बिजली की मांग में उछाल

**3352. श्री गौरव गोगोईः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अनुसार वर्ष 2041 तक असम में बिजली की मांग बढ़कर सात हजार मेगावाट हो जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) असम में वर्तमान में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और भावी मांग को पूरा करने के लिए कितनी क्षमता वृद्धि की योजना बनाई गई है;

(ग) असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा इस बढ़ती मांग के प्रबंधन में किन प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है जिनमें अवसंरचना पारेषण हानि और वित्तीय अड़चनों का व्यौरा शामिल है;

(घ) राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने, पारेषण और वितरण अवसंरचना के उन्नयन और उपभोक्ताओं को सस्ती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने रहे हैं, और

(ङ) क्या सरकार असम की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और अंतर्राजीय विद्युत क्रय समझौतों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित 20वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2041-42 के लिए असम राज्य की ऊर्जा आवश्यकता और अधिकतम मांग क्रमशः 33,430 एमयू और 7,006 मेगावाट होने का अनुमान है।

(ख) : असम के लिए वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता (आवंटन आधारित) 2,367 मेगावाट है। सोत-वार विवरण अनुबंध पर है। सीईए के सहयोग से असम की विद्युत यूटिलिटी द्वारा असम के लिए किए गए संसाधन पर्याप्तता (आरए) अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2034-35 में असम राज्य द्वारा आवश्यक अनुमानित अनुबंधित क्षमता 8,292 मेगावाट होने की संभावना है, जिसमें कोयले से 2,499 मेगावाट, गैस से 771 मेगावाट, जलविद्युत से 1,168 मेगावाट, सौर से 3,304 मेगावाट, पवन से 550 मेगावाट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्टोरेज कांट्रोल के लिए 915 मेगावाट, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) सोतों से 1,495 मेगावाट तथा अल्पावधि/मध्यमावधि/बैंकिंग व्यवस्था के लिए 1,139 मेगावाट की भी आवश्यकता हो सकती है।

(ग) से (ड) : असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के अनुसार, असम में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने में कोई चुनौती नहीं है। एपीडीसीएल द्वारा विद्युत क्रय समझौतों के माध्यम से 2,500 मेगावाट की पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, एपीडीसीएल आगामी वर्षों में असम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एपीजीसीएल) लोअर कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट से 120 मेगावाट, एनएचपीसी लोअर सुबानसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट से 208 मेगावाट, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) घाटमपुर से 495 मेगावाट ताप विद्युत, एनटीपीसी तालचेर से 154 मेगावाट और भूटान के पुनात्सांगछ हाइड्रो प्लांट से 173 मेगावाट विद्युत खरीदेगी। इसके अलावा, शक्ति ख(iv) नीति के अंतर्गत कोयला आवंटन का उपयोग करते हुए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से 500 मेगावाट ताप विद्युत की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, असम में विद्युत उत्पादन बढ़ाने, पारेषण और वितरण अवसंरचना का उन्नयन करने और उपभोक्ताओं को सस्ती विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन:

- क. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के वित्तपोषण के माध्यम से “मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रकोल्पो” के अंतर्गत राज्य में 1000 एमडबल्यूपी (750 एमडबल्यूएसी) सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्यान्वयन।
- ख. एपीडीसीएल और एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के गठन द्वारा 1,000 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं का विकास।
- ग. एपीडीसीएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के गठन द्वारा 1,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास।
- घ. एपीडीसीएल और ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम का गठन करके 250 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना।
- ड. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं में रुफटॉप सोलर प्लांट की संस्थापना। दिनांक 13.03.2025 तक लाभार्थियों की संख्या 9,098 है और कुल संस्थापित क्षमता 28 मेगावाट है।
- च. ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी परियोजना से 70 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, बिल्ड-ऑन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित की जाएगी।
- छ. ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, जिसे बिल्ड-ऑन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।
- ज. ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, जिसे बिल्ड-ऑन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।
- झ. ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 15 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, जिसे बिल्ड-ऑन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।

(ii) वितरण अवसंरचना को उन्नत करने के लिए, असम सरकार ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) स्कीम के तहत असम में “असम वितरण प्रणाली संवर्धन और हानि न्यूनीकरण” परियोजना शुरू की है, जिसे 3,284.04 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के लिए “एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)” द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

इस परियोजना के अंतर्गत असम के विभिन्न क्षेत्रों में 196 नए 33/11 केवी सब-स्टेशनों के साथ-साथ 2,415 किलोमीटर नई 33 केवी लाइन और 2,272 किलोमीटर नई 11 केवी लाइन का निर्माण किया जा रहा है। 3,673 नए वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) के साथ उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) और संबंधित 1,683 किलोमीटर नई 11 केवी लाइनों का कार्य भी प्रगति पर है।

(iii) इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये का सकल बजटीय समर्थन प्राप्त होगा। इस स्कीम के अंतर्गत, असम राज्य के लिए 7,444 करोड़ रुपये की लागत के स्मार्ट मीटरिंग और वितरण अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों में अन्य कार्यों के साथ-साथ राज्य में 63.64 लाख उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, 77,547 वितरण ट्रांसफार्मर और 2,782 फीडर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वितरण अवसंरचना कार्यों में निम्न दाब (एलटी) नंगे कंडक्टरों की रि-कंडक्टरिंग, उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन, 11 केवी फीडरों का विभाजन, पुराने 11 केवी और 33 केवी कंडक्टरों को प्रतिस्थापित करना और नए 33 केवी फीडरों को जोड़ना शामिल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) ने इस स्कीम के अंतर्गत ~41% की वास्तविक प्रगति हासिल की है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3352

अनुबंध

फरवरी, 2025 तक असम के लिए मेगावाट में वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता (आवंटन के आधार पर)

स्वामित्व /क्षेत्र	मोड-वार ब्रेकअप								कुल योग	
	ताप					परमाणु	नवीकरणीय			
	कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल		हाइड्रो	आरईएस		
राज्य	0.00	0.00	306.36	0.00	306.36	0.00	100.00	5.01	105.01	411.37
निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.44	198.44	198.44
केन्द्रीय	874.52	0.00	435.56	0.00	1,310.08	0.00	422.08	25.00	447.08	1,757.16
उप-योग	<b>874.52</b>	<b>0.00</b>	<b>741.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616.44</b>	<b>0.00</b>	<b>522.08</b>	<b>228.45</b>	<b>750.53</b>	<b>23,66.97</b>

नोट: इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन के गैर-आवंटित पूल से 302 मेगावाट विद्युत असम को आवंटित की गई है।

\*\*\*\*\*